Centenary Year
All India Railwaymen's Federation

Soon after the evolution of the Trade Union Movement in the world, several small unions started coming up in the Indian Railways during the British Regime. The basic reason behind formation of such unions was serious racial discrimination being meted out to the Indian Railway Workers by the Britishers in respect of pay-scales and other service conditions as Indian Workers were being granted lower pay-scales than the pay scales for the Europeans and Anglo-Indians for doing the same work.

It was, therefore, felt necessary by the National leaders that, a National Trade Union Centre needs to be established to coordinate with different Railway Unions in the Indian Railways, which was in different shape during the British Era. Consequent upon this, the process of formation of an All India Body of the Railwaymen started from the year 1922, and finally "All India Railwaymen's Federation" was established on 24.04.1924 as a National Centre of the Railway Unions functioning in different Railways in India.

Railways being a strategic industry, it was very important for the freedom struggle to involve the Railwaymen in the agitations against the British Imperialism. Owing to several agitations and struggles by the Indian Railwaymen under the umbrella of AIRF, Railway Board started negotiations with AIRF from the year 1928, and half-yearly meetings were held between AIRF and Railway Board, which was then headed by the Chief Commissioner of Railways. As a result of these negotiations, there had been several achievements to the credit of AIRF and its affiliated unions to improve service conditions of the Railwaymen.

During the Second World War, the inflation highly eroded real wages of the workers, as such AIRF agitated this issue, and consequently Dearness Allowance was introduced and paid to the employees for the first time.

AIRF was bitterly opposed to racial discrimination by the Britishers and opposed the lower pay-scales being granted to the Indian Workers than the pay-scales of the Europeans and Anglo-Indians for doing the same job. It was the outcome of AIRF's strong agitations and opposition that the First Pay Commission was formed by the British Government in the year 1946, which submitted its report in May 1947 and removed the said discrimination between the pay-scales of the Indian Workers and Anglo-Indians.

AIRF was led by various Veteran National Leaders, like Late Shri Rai Sahib Chandrika Prasad as President AIRF(from 17.02.1925 to 18.12.1928), Late Shri Mukund Lal Sarkar as General Secretary AIRF(from 16.02.1925 to 25.11.1927). Late Shri V.V. Giri as General Secretary AIRF (from 26.11.1927 to 04.07.1937) and also as President AIRF (from 25.11.1944 to 05.05.1946), Lok Nayak Jayaprakash Narain as President AIRF(from 07.06.1947 to 27.06.1953), Late Shri Priya Gupta as General Secretary AIRF(from 23.08 1968 to 29.05.1975) and also as President AIRF (from 07.07.1976 to 12.08.1979), Late Shri George Fernandes as President AIRF (from 20.10.1973 to 06.07 1976), Late Shri J.P. Chaubey as General Secretary AIRF (from 30.05.1975 to 03.09.2008), Late Shri Umraomal Purohit as President AIRF (from 31.08.1980 to 27.02.2014). Until 1947 AIRF was able to unify the entire Railway Trade Union Movement into one union on each Railway and one Federation for whole of the Indian Railways. It was after 1947 that the Congress Party floated its own Central Trade Union - Indian National Trade Union Congress and formed its Federation in the Indian Railways in the name of National Federation of Indian Railwaymen in the year 1948.

During post-Independence era also, AIRF, being the largest organization of the Indian Railways, continued its sustained struggle for socio-economic upliftment of the Railwaymen by way of improvement in the Wages, Perks Allowance and Promotional Prospects etc., thereby improving service conditions of various categories of workers.

AIRF has spearheaded three National Strikes of 1960, 1968 and 1974 (earlier two strikes - 1960 and 1968 of the Central Government Employees, and 1974 of the Railwaymen). Fortunately, all the three strikes were supported by the Great Statesman - Late Shri Atal Bihari Bajpayee. 1974 strike, headed by Shri George Fernandes, brought down the mighty Government of that time. So, AIRF has a history of struggles.

The First Railway Workers Classification Tribunal was formed by the Ministry of Railways in the year 1979, that paved the way for upgradation of various categories of Technical Staff in Indian Railways from Unskilled to Semi-Skilled and Semi-Skilled to Skilled Workers. Subsequently, Cadre Restructuring Committees were formed in the years 1984, 1993, 2003 and 2013. These Cadre Restructuring Committees resulted in improvement in promotional avenues for almost all the categories of the Railwaymen, and AIRF has all along been a Member of these Cadre Restructuring Committees.

For improvement in Minimum Wage and Pay-Scales and also to secure Minimum Wage, as per 15th ILO Convention, Successive Pay Commissions were also formed by the Government, on the demand of AIRF, in the years 1946, 1957, 1970, 1983, 1994, 2006 and 2016.

AIRF is completing 100 years of its formation on 24.04.2024, and its General Council has decided to celebrate the Centenary Year in a befitting manner at New Delhi. The Department of Posts is delighted to issue a Commemorative Postage Stamp on Centenary Year All India Railwaymen's Federation.

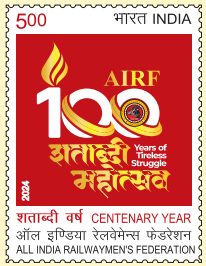
Credits:

Stamp/FDC/Brochure /Cancellation Cachet : Smt. Nenu Gupta

Text : Referenced from content provided by Proponent

भारतीय डाक
India Post

डाक विभाग
Department of Posts



ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन
ALL INDIA RAILWAYMEN'S FEDERATION
शताब्दी वर्ष CENTENARY YEAR



विवरणिका BROCHURE

शताब्दी वर्ष
ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन

विश्व में व्यापार संघ (ट्रेड यूनियन) आंदोलन की शुरुआत के कुछ समय बाद से ही, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय रेलवे में कई छोटे संघ बनने लगे। ऐसे संघों के गठन का मूल कारण वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों के मामले में अंग्रेजों द्वारा भारतीय रेलवे कामगारों के साथ किया जाने वाला गंभीर जातिगत भेदभाव था क्योंकि भारतीय कामगारों को समान काम के लिए यूरोपीय लोगों और एंग्लो–इंडियन समुदाय की तुलना में कम वेतनमान दिया जा रहा था।

अतः राष्ट्रीय नेताओं को यह आवश्यकता महसूस हुई कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय रेलवे, जिसका संगठनात्मक ढांचा उस समय अलग स्वरूप का था, के विभिन्न रेलवे संघों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापार संघ केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 1922 से रेलकर्मियों के एक अखिल भारतीय निकाय के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई और अंततः 24.04.1924 को भारतीय रेलवे की विभिन्न शाखाओं में कार्यरत रेलवे संघों के राष्ट्रीय केंद्र के रूप में "ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (अखिल भारतीय रेलवेमेन्स फेडरेशन)" की स्थापना की गई।

रेलवे के कार्यनीतिक उद्देश्य से महत्वपूर्ण उद्योग होने के कारण स्वतंत्रता संग्राम हेतु ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आंदोलनों में रेलकर्मियों को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण था। एआईआरएफ के नेतृत्व में भारतीय रेलकर्मियों द्वारा किए गए आंदोलनों और संघर्षों के फलस्वरूप रेलवे बोर्ड ने वर्ष 1928 से एआईआरएफ के साथ बातचीत शुरू की तथा एआईआरएफ और रेलवे बोर्ड के बीच अर्ध–वार्षिक बैठकें आयोजित की गईं, जिनकी अध्यक्षता रेलवे के मुख्य आयुक्त द्वारा की जाती थी। इन वार्ताओं के परिणामस्वरूप, एआईआरएफ और उससे संबद्ध संघों ने रेलकर्मियों की सेवा स्थितियों में सुधार की दिशा में अनेक उपलब्धियां हासिल की।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, महंगाई से कामगारों का वास्तविक वेतन बहुत घट गया था, ऐसे में एआईआरएफ ने इस मुद्दे को उठाया जिसके परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते की शुरुआत की गई एवं कर्मचारियों को पहली बार इसका भुगतान किया गया।

एआईआरएफ ने ब्रिटिश शासकों द्वारा किए जा रहे जातिगत भेदभाव का कड़ा विरोध किया और समान काम के लिए भारतीय कामगारों को यूरोपीय लोगों और एंग्लो–इंडियन समुदाय से कम वेतनमान दिए जाने का विरोध किया। यह एआईआरएफ के प्रबल आंदोलन एवं विरोध का ही परिणाम था कि वर्ष 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम वेतन आयोग का गठन किया गया, जिसने मई 1947 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और भारतीय कामगारों तथा एंग्लो–इंडियन समुदाय के वेतनमान के बीच हो रहे भेदभाव को मिटा दिया।

एआईआरएफ का नेतृत्व विभिन्न अनुभवी राष्ट्रीय नेताओं ने किया। इस सूची में एआईआरएफ के अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री राय साहब चंद्रिका प्रसाद (17.02. 1925 से 18.12.1928 तक), एआईआरएफ के महासचिव के रूप में स्वर्गीय श्री मुकुंद लाल सरकार (16.02.1925 से 25.11.1927 तक)। एआईआरएफ के महासचिव (26.11.1927 से 04.07.1937 तक) और साथ ही एआईआरएफ के अध्यक्ष (25.11.1944 से 05.05.1946 तक) के रूप में स्वर्गीय श्री वी.वी. गिरि, एआईआरएफ के अध्यक्ष के रूप में लोक नायक जयप्रकाश नारायण (07.06.1947 से 27.06.1953 तक), एआईआरएफ के महासचिव (23.08 1968 से 29.05. 1975 तक) और साथ ही एआईआरएफ के अध्यक्ष (07.07.1976 से 12.08.1979 तक) के रूप में स्वर्गीय श्री प्रिया गुप्ता, एआईआरएफ के अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडीस (20.10.1973 से 06.07 1976 तक), एआईआरएफ के महासचिव के रूप में स्व. श्री जे.पी.चौबे (30.05.1975 से 03.09.2008 तक), एआईआरएफ के अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय श्री उमरावमल पुरोहित (31.08.1980 से 27.02.2014 तक) का नाम शामिल है। 1947 तक एआईआरएफ, पूरे रेलवे व्यापार संघ आंदोलन को एकजुट करने में सक्षम था जिसके अंतर्गत रेलवे की प्रत्येक शाखा के लिए एक यूनियन और पूरे भारतीय रेलवे के लिए एक फेडरेशन का गठन शामिल था। वर्ष 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ने स्वयं का भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस के नाम से एक केंद्रीय व्यापार संघ बनाया और वर्ष 1948 में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन के नाम से भारतीय रेलवे में अपने फेडरेशन का गठन किया।

स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा संगठन होने के नाते, एआईआरएफ ने वेतन, भत्तों और पदोन्नति की संभावनाओं आदि में सुधार के माध्यम से रेलकर्मियों के सामाजिक–आर्थिक उत्थान के लिए अपना संघर्ष जारी रखा, जिससे विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की सेवा शर्तों में सुधार हुआ।

एआईआरएफ ने 1960, 1968 और 1974 की तीन राष्ट्रीय हड़तालों का नेतृत्व किया (पहली दो अर्थात् 1960 और 1968 की हड़तालें, केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा और 1974 की हड़ताल, रेलवेकर्मियों द्वारा की गई थी)। इन तीनों हड़तालों को महान राजनेता – स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी का समर्थन प्राप्त था। श्री जॉर्ज फर्नांडीस की अध्यक्षता में 1974 की हड़ताल ने तत्कालीन सरकार को गिरा दिया। अतः एआईआरएफ का इतिहास विभिन्न मुद्दों पर संघर्ष की गाथाओं से भरा है।

प्रथम रेलवे श्रमिक वर्गीकरण अधिकरण का गठन वर्ष 1979 में रेल मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसने भारतीय रेलवे में तकनीकी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों को अकुशल से अर्ध–कुशल और अर्ध–कुशल से कुशल श्रमिकों में अपग्रेड करने का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद, वर्ष 1984, 1993, 2003 और 2013 में संवर्ग पुनर्गठन समितियों का गठन किया गया। इन संवर्ग पुनर्गठन समितियों के परिणामस्वरूप लगभग सभी श्रेणियों के रेलकर्मियों के लिए पदोन्नति के अवसरों में सुधार हुआ और एआईआरएफ हमेशा से इन संवर्ग पुनर्गठन समितियों का सदस्य रहा है।

न्यूनतम मजदूरी और वेतनमान में सुधार के लिए और 15वें आईएलओ सम्मेलन (कन्वेंशन) के अनुसार न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित किए जाने संबंधी एआईआरएफ की मांग पर, सरकार द्वारा वर्ष 1946, 1957, 1970, 1983, 1994, 2006 और 2016 में वेतन आयोगों का गठन भी किया गया।

24.04.2024 को एआईआरएफ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। फेडेरेशन की सामान्य परिषद ने शताब्दी वर्ष का जश्न इसके महत्व के अनुरूप नई दिल्ली में मनाने का निर्णय लिया है। डाक विभाग, ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन के शताब्दी वर्ष पर स्मारक डाक–टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभारः–

डाक टिकट/प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका/विरूपण कैशे : सुश्री नीनू गुप्ता

पाठ : प्रस्तावक से प्राप्त सामग्री के आधार पर

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्य	:	500 पैसे
Denomination	:	500 p
मुद्रित डाक टिकटें	:	304100
Stamps Printed	:	304100
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबाद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http:/www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार । डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamps, Miniature Sheets, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 5-00